



# भारत का दावत

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446]  
No. 446]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 1991/शावा 23, 1913  
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 1991/SRAVANA 23, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या हो जाती है किससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वित्त संत्राय  
(आयात कार्य विभाग)

(वैकिंग प्रभाग)

ज्ञापन

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1991

दिनांक प्रणाली पर मिर्जिन

का.आ. 519(अ).—विभिन्ने दो दावकों में इमरी वित्तीय प्रणाली के  
भौगोलिक क्वरेज और वित्तीय प्रसार में अप्राप्तार्थ विस्तार हुआ है।  
वित्तीय क्षेत्र का विकास एक मुख्य उत्तराधीन है। शोध दर्शन, दूसारी वचनदर  
में, विशेष तीर पर पारिवारिक क्षेत्र में, महत्वपूर्ण यात्राएँ की हैं। तथापि,  
हाल के वर्षों में प्रणाली में कुछ ग्राम्य अनुनयनों और कमज़ोरियाँ देखने में  
आई हैं तथा इन पर ध्यान दिया जाना; जहां वे नाकि वित्तीय प्रणाली और  
अविक कुण्ठल तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था का विकास करते में अपनी  
भूमिक निभा सके।

2. अतः वित्तीय प्रणाली की संरचना, संगठन, कार्यों और प्रक्रियाओं के  
सभी पहलुओं की जांच करने के लिए भारत वरकार ने एक उच्च स्तरीय

समिति गठित करने एक निर्णय लिया है। समिति में निम्नलिखित  
जामिल होंगी:—

1. श्री एम. नरसिंहम	प्राध्यकार
2. उपर्युक्त भारतीय रिजर्व बैंक (वैकिंग परिवापत)	सदस्य
3. अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक	सदस्य
4. अध्यक्ष भारतीय ओर्डोरिंग विकास बैंक	सदस्य
5. अध्यक्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विवेष नियम	सदस्य
6. एम.सन् व्याक	सदस्य
7. श्री वाई एवं मार्टिन गेन	सदस्य
8. श्री मृणाल उत्ता चौधरी	सदस्य
9. अपर सचिव (वैकिंग)	सदस्य सचिव
3. समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे:—	

(1) दिनांक प्रणाली को विद्यमान संरचना और उनके विभिन्न संघटकों  
की जांच करना और प्रणाली की कार्य कुण्ठलता और प्रभावकारिता  
तथा विशेष रूप में वाणिजिक बैंकों और वित्तीय स्थानों के

कार्यपालक में विनाशका, नशीलें और नामांडन के समर्थन में सुधार लाने के लिए गुम्भाव देता।

(2) संगठनात्मक प्रणालियां और प्रक्रियाओं तथा प्रबंधनीय नीतियां में सुधार और उनके प्रयोगशाला के लिए नियां नियां करना;

(3) प्रणाली में और अधिक प्रतियोगितात्मक अवस्था नामों के लिए नियां नियां करना ताकि बैंक और वित्तीय संस्थाएं अव्यवस्थित की अपेक्षा उसकी तुला ले पायें। याकारात्मक नामों की परिवर्तन कार्यालय द्वारा ने दूसरे में मात्रम ही सके;

(4) वित्तीय संस्थाओं के तुरंत छावें की जागत, संरचना और पर्याप्तता की जांच करना समेत इस संघर्ष में उपयुक्त नियां नियां करना;

(5) वित्तीय प्रणाली में विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं की संरचना भूमिकाओं की समीक्षा करना और उनके संयुक्त विकास के लिए नियां नियां करना;

(6) वित्तीय धन से, वित्तीय धन से वित्तीय वैकां और मावधि अपेक्षात्मक संस्थाओं में, वित्तीय नियां नियां में गंभीर वर्तमान पर्यावरण अवस्थाओं की समीक्षा करना और उत्तम तथा कार्यालय व्यवेक्षण मुनिषिवन करने के लिए नियां नियां करना;

(7) वर्तमान विधायी केमेंट की समीक्षा करना और नियां नियां को कार्यात्मक करने के लिए आवश्यक संशोधनों का सुझाव देना, जिनके संघर्ष में विधायी परिवर्तन अपेक्षित हो सकते हैं;

(8) किसी अन्य विषय पर नियां नियां करना जिसे समिति जोन व नियां के लिए संगत समझे या कोई संबंध नामना जिसे भारत सरकार द्वारा, वित्तीय धन से नियां नियां को मेंजा गया हो।

4 समिति अपनी रिपोर्ट 15 नवंबर, 1991 तक प्रस्तुत कर देगी। अनलवर्ना, किसी विशिष्ट मामले पर समिति अन्तर्राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है।

[स. एफ. 16(5) 91-बी.ओ.1]

के जै. रेडी, प्रपर नियां

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)  
(Banking Division)  
MEMORANDUM

New Delhi, the 14th August, 1991  
COMMITTEE ON THE FINANCIAL SYSTEM

S.O. 519(E).—The last two decades have seen a phenomenal expansion in the geographical coverage and financial spread of our financial system. The development of the financial sector is a major achievement and it has contributed significantly to the increase in our savings rate, especially of the household sector. In recent years, however, certain rigidities and weaknesses have developed in the system and these have to be addressed to enable the financial system to play its role in ushering in a more efficient and competitive economy.

2 It has, therefore, been decided by the Government of India to set up a High Level Committee to examine all aspects relating to the structure, organisation, functions and procedures of the financial system. The Committee will consist of the following:

1. Shri M. Narasimham	Chairman
2. Deputy Governor, RBI (Banking Operations)	Member
3. Chairman, State Bank of India	Member
4. Chairman, IDBI	Member
5. Chairman, ICICI	Member
6. Shri Manu Shroff	Member
7. Shri Y. H. Malegam	Member
8. Shri Mrinal Datta-Chaudhuri	Member
9. Additional Secy. (Banking)	Member-Secretary

3. The terms of reference of the Committee will be as follows.—

- (i) To examine the existing structure of the financial system and its various components and to make recommendations for improving the efficiency and effectiveness of the system with particular reference to the economy of operations, accountability and profitability of the commercial banks and financial institutions;
- (ii) To make recommendations for improving and modernising the organisational systems and procedures as well as managerial policies;
- (iii) To make recommendations for infusing greater competitive vitality into the system so as to enable the banks and financial institutions to respond more effectively to the emerging credit needs of the economy;
- (iv) To examine the cost, composition and adequacy of the capital structure of the various financial institutions and to make suitable recommendations in this regard;
- (v) To review the relative roles of the different types of financial institutions in the financial system and to make recommendations for their balanced growth;
- (vi) To review the existing supervisory arrangements relating to the various entities in the financial sector, in particular the commercial banks and the term lending institutions and to make recommendations for ensuring appropriate and effective supervision;
- (vii) To review the existing legislative framework and to suggest necessary amendments for implementing the recommendations that may require legislative change;
- (viii) To make recommendations on any other subject matter as the Committee may consider germane to the subject of enquiry or any related matter which may be specifically referred to the Committee by the Government of India.

4. The Committee will submit its report by 15th November, 1991. The Committee may, however, submit an interim report on any specific matter.

[No. F. 16(5)91-B.O.1]  
K. J. REDDY, Addl. Secy.